© 2016 IJSRSET | Volume 2 | Issue 2 | Print ISSN: 2395-1990 | Online ISSN : 2394-4099

वर्तमान परिपेक्ष्य में भारतीय–राजशास्त्र की प्रासंगिकता

प्रतिमा कुमारी
पूर्व शोध–छात्रा,
संकाय सामाजिक विज्ञान,
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार, भारत।

''अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम्।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुक्बकम्।।''

वैदिक संस्कृत साहित्य का इतिहास

प्रस्तावना– वर्तमान परिपेक्ष्य में जो भारतीय राज्यव्यवस्था चल रही है, प्राचीनकाल की राज्यव्यवस्था कही– न कही वर्तमानकाल की राजव्यवस्था से कही बेहतर थी। अतः वर्तमान परिपेक्ष्य में भारतीय राजव्यवस्था की जो प्रासंगिकता है, उसे मैं अपने शब्दों में व्यक्त कर रही हूँ।

राजव्यवस्था का तात्पर्य– विष्व में भारत प्रजातन्त्र का एक बड़ा उदाहरण है, इसकी राजव्यवस्था भी अपने आप में विलक्षण है। वर्तमान में उड़ीसा से लेकर गुजरात तक, जम्मू–कष्मीर से लेकर तमिलनाडु तक 29 राज्यों को तथा उनकी परम्पराओं को, कलाओं को तथा विषिष्ट धरोहरों को इतिहास के साथ वर्तमान को जोड़ते हुए राजव्यवस्था कायम किया गया है। अतः यह भारत अपने आप में अद्भुत है। जो विभिन्न वर्ग, समुदाय, जाति, धर्म, दर्षन को एकसूत्र में पिरोए हुए है।

इस राजव्यवस्था की शक्ति ''प्रजा'' है। प्रजा के हाथ में राज्यषासन चलाना होता है। प्रजा अपने मतों द्वारा राज्य और केन्द्र में सरकार का चयन करती है। ये सरकारें जनता के विविध अधिकारों को ध्यान में रखते हुए तथा उनके हितों के लिए योजनाओं का आयोजन करती है।

अतः इस राजव्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए तीन अंगो से युक्त राज्यषासन के स्वरूप का निर्माण किया गया है।

1. **विधायिका**
2. **कार्यपालिका**
3. **न्यायपालिका**

विधायिका ग्राम के सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति तक जनता का नेतृत्व करने वाले प्रजातंत्र की सेवा करने वाले तथा प्रजा के हितों को ध्यान में रखकर समय–समय पर षिक्षा, स्वास्थ्य,

बिजली पानी जैसी मूलभूत आवष्कताओं की सुविधा केन्द्रीय तथा राजकोष से धन खर्च कर उपलब्ध कराते है।

उपर्युक्त सारी सुविधाओं में कार्यपालिका की अहम भूमिका होती है। विधायिका के द्वारा लिए गये निर्णय को जनता तक पहुँचाने का काम कार्यपालिका का है। **जैसे–जन–धन योजना, उज्जवला योजना, मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल योजना, विघुत योजना इत्यादि।**

इन सभी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कार्यपालिका नियुक्त किये गये कार्यालयी सदस्यों को भेज कर अथवा प्रचारित कर योजनाओं से आम जनता को जोड़ती है, इन योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुँचता है।

न्यायपालिका भारतीय संविधान के अनुसार राजव्यवस्था का प्रमुख अंग हैः यह पूर्णतया स्वतंत्र है। निचली अदालत के अधिवक्ता से लेकर उच्चतम न्यायालय के न्यायधीष–तक की न्यायप्रणाली न्यायपालिका कहलाती है। न्यायपालिका का अधिकार सर्वमान्य होता है।

भारत में सर्वोच्च न्यायालय एक है तथा प्रत्येक राज्य में एक–एक मुख्य पीठ है। जनसंख्या के अनुसार कुछ जगहों में खण्डपीठ की व्यवस्था भी की गयी है। **जैसे–भोपाल तथा ग्वालियर, मुम्बई तथा नागपुर** किन्तु कुछ राज्यों में खण्डपीठ नहीं है। न्यायपालिका कार्यपालिका तथा विधायिका की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण रखती है, जो कि जनता के हित में होती है। न्यायप्रणाली जनता की सुरक्षा को विष्वसित करती है।

वर्तमानकालीन राजव्यवस्था का स्वरूप एवं विवेचन– भारत में तीन अंगो से चलने वाली राज्यव्यवस्था 29 राज्यों में विभक्त है जो कि जनता के लिए जनता द्वारा जनता को समर्पित है। हमारी वर्तमान राजव्यवस्था गुण व दोषों का सम्मिश्रण है। आज सरकार देष के नागरिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं को लागू कर रही हैं जिसके लिए देष अब तक तरसता ही रह गया था। इन योजनाओं में **प्रधानमंत्री उज्जवला योजना** के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को निःषुक्ल एलपीजी कनेक्षन बाँटे गये, जिससे करोड़ो महिलाओं के चेहरें पर मुस्कुराहट और स्वास्थ्य दुरुस्त करने का काम किया गया है। **बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं सुकन्या समृद्धि योजना** के तहत बालिकाओं की षिक्षा विवाह इत्यादि की समस्या दूर की जा रही है ताकि देष की हर बेटी आत्मनिर्भर बने और तरक्की करे। **स्वच्छ भारत अभियान के** तहत देष को स्वच्छ करने की जो पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने की वैसा पहले कभी किसी ने नही सोचा था। आज देष स्वच्छता के प्रति सजग हो गया है प्रत्येक स्थान पर सफाई देखी जा रही है, जिससे बिमारीयों का खतरा कम हो रहा है। इसी योजना के तहत देषभर के गाँवों में करीब 4 करोड़ घरों में शौचालयों का निर्माण हुआ है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब से गरीब इंसान भी अपना खुद का घर होने का सपना देख सकता है। **प्रधानमंत्री जनधन योजना** के तहत गरीबों को बैंक में मुफ्त में खाता खोलने का मौका दिया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के चलते भ्रष्टाचार के रास्ते को बंद किया।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के द्वारा सरकार हर गाँव के हर घर तक बिजली पहुँचाने में लगी है इसके अतिरिक्त भारत सरकार के नोटबंदी का फैसला आंतरिक अर्थव्यवस्था में फैले कालेधन के खिलाफ सकारात्मक कदम रहा। सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान कर लगाया जाएगा, जिससे देष के सभी नागरिकों को सीधे फायदा तो मिलेगा ही, साथ ही कालाबाजारी तथा चोरी पर भी रोक लगेगी। **मेक इन इंडिया** के तहत देष को मैन्युफैक्चरिंग का केन्द्र बनाना है। इसके अलावा सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को **तीन तलाक** से मुक्ति दिलाने का भी कार्य किया है। यही नहीं सरकार ने गरीब मुसलमानों के लिए सस्ती **हज यात्रा** की पहल भी कि है। इन मुख्य कार्यो के अलावा और भी कार्य सरकार कर रही है। जिससे हमारे देष की स्थिति सुदृढ़ हो सके और हमारा देष विकासषील की श्रेणी से निकलकर विकसित देषों की श्रेणी में आ जाये।

इन सभी गुणों के अलावा हमारी वर्तमान राजव्यवस्था में कई दोष भी पाये जा रहे है। जैसे– पेयजल की समस्या आज भारत के लगभग 20 से 25 राज्यों में पेयजल की समस्या बनी हुई है। यहाँ के लोग टैकरों द्वारा जल मँगाकर अपना जीवन–यापन करने पर मजबूर है। अतः राज्यसरकार और केन्द्रसरकार दोनों को चाहिए की देष के जलसंकट को पूर्णतया दूर करने का प्रयास करे, नदियों के जल को गंदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए नदियों के जल को स्वच्छ रखने के लिए कोई अहम कदम उठाये जिससे पेयजल की समस्या का निराकरण हो सके।

आदर्ष ग्राम योजना के तहत हर सांसद को पाँच गाँव को गोद लेने की व्यवस्था है जिसमें 2016 तक प्रत्येक सांसद एक–एक गाँव को विकसित बनाये परन्तु आज तक एक भी गाँव आदर्ष गाँव की श्रेणी में नहीं आया।

आज पेट्रोल–डीजल के दाम से देष में हाहाकार मचा हुआ है।–

सरकार की लगातार कोषिषों के बावजूद कष्मीर घाटी में आज भी अषांति और हिंसा का माहौल जारी है।

मुख्य समस्याओं में भारत में षिक्षा की समस्या भी है। वर्तमान परिपेक्ष्य में मैकाले पद्धति के अनुसार षिक्षा प्रणाली चल रही है, जो कि राजव्यवस्था को पूर्णतया पंगु बना रही है। क्योंकि भारत में विष्वविद्यालयों द्वारा कौषलप्राप्ति की अपेक्षा उपाधियाँ बाँटी जा रही है, जिसके कारण **बेरोजगारी, कुषलता का अभाव, भविष्य के प्रति चिन्ता सरकार के प्रति विच्छोह, आक्रोष, अपने आप पर आत्मविष्वास की कमी** ऐसे दोष षिक्षा प्रणाली में दिखायी दे रहे है। इस प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार और राज्यसरकार दोनों को चाहिए कि कौषल विकास योजना के तहत प्रत्येक शैक्षिणिक संस्था को प्रायोगिक, जीवन परक, व्यवहारिक प्रषिक्षण केन्द्रो में परिवर्तित करे ताकि ये युवा अपनी कुषलता से अभियांत्रिक तकनीकियों से निखरकर विष्व में अपनी कला को विकसित प्रचारित तथा रोजगार परक बनाये। क्योंकि आज तक जितनें भी अविष्कार हुए है वे अधिकतर पाष्चात्य वैज्ञानिकों के द्वारा ही हुए है जैसे–

अविष्कार	अविष्कार का नाम	देष
पेण्डुलम घड़ी	क्रिष्चन हाइजेन्स	नीदरलैण्ड
सिलाई मषीन	एलियास होवे	संयुक्त राज्य अमेरिका
फाउण्टेन पेन	लेविस ई. वाटरमैन	संयुक्त राज्य अमेरिका
एलसीडी	होफमन लारोष	स्विजरलैण्ड
धुलाई मषीन	एल्वा फिषर	संयुक्त राज्य अमेरिका
मोटरसाईकल	एडवर्ड बटलर	इंग्लैण्ड
थर्मामीटर	गैलेलियो गैलिली	इटली
गुकत्वाकर्षण का सिद्धान्त	सर आइजेक न्यूटन	इंग्लैण्ड
साईकल	कार्ल डी.वॉन सौरब्रोन	जर्मनी

इसका मतलब यह नहीं कि हमारें देष में प्रतिभाओं की कमी है, कमी है तो षिक्षा प्रणाली की। यदि हमारी षिक्षा प्रणाली के दोष समाप्त हो जाए तो फिर से भारत युवाओं का देष, ज्ञानियों का देष, वैज्ञानिकों का देष कहलाने लगेगा। भारत में मात्र उपग्रह क्षेत्र में कुछ विकास देखे जा रहे है जिसमें भारतीय आधुनिक वैज्ञानिकों का योगदान है। यह बड़े खेद की बात है कि हमारे भारत में षिक्षा प्रणाली इस तरह की है जिससे हम ऋषि परम्परा, ज्ञान परम्परा विज्ञान परम्परा, अनुसंधान परम्परा, संस्कार परम्परा, कला परम्परा, संस्कृति परम्परा, उत्सव परम्परा, इन सभी परम्पराओं से दूर होते जा रहे है। आज का विद्यार्थी अगर गुमराह हो रहा है तो इसमें उसका कम सरकार और समाज का अधिक दोष है उसके राम–कृष्ण, सुभाष–गाँधी जैसे अदर्ष न होकर रावण–कंष जैसे लोग आदर्ष बने है। इन सबका कारण दोषपूर्ण पाठ्यक्रम दोषपूर्ण षिक्षा प्रणाली है, इसकों दूर करने का दायित्व भारत के राज्य तथा केन्द्र षिक्षामंत्री का है।

भारतीय षिक्षा प्रणाली के बदूतर स्थिति के कारण भारत के करोड़ो युवाओं को नुकसान हो रहा है, उनका भविष्य संकट में नजर आ रहा है। दिन प्रतिदिन उनकी प्रतिभा, उनका कौषल क्षीण होता जा रहा है। जिसके कारण M.B.A, Ph.D इत्यादि उच्चस्तरीय उपाधियों को प्राप्त करके भी लाखों की तादाद में ये युवा चतुर्थश्रेणी का कर्मचारी बनना चाहते है। इसका तात्पर्य है कि इन दषकों में भारत में रोजगार की कमी आयी है। इन समस्याओं को देखते हुए हम कह सकते है कि भारत की षिक्षण संस्थाएँ कुषल नागरिक का निर्माण नहीं कर पा रही है, इन्ही सामाजिक गतिविधियों के कारण कही जनाक्रोष तो कही हड़ताल तो कही दंगे होते है, जिसे परिणामस्वरूप प्रजातांत्रिक सम्पत्रियों का नुकसान होता है जो राज्यसरकार और केन्द्रसरकार के विकास में बहीत बड़ी बाधा है। एक गरीब परिवार का युवा प्रतिभा सम्पन्न होता हुआ भी आर्थिक अभाव के कारण महँगे–महँगे आवेदन पत्रों को पूर्ण नहीं कर पाता और रोजगार से बंचित रह जाता है आज देष में भ्रष्टाचार बांचित रह जाता है। आज देष में भ्रष्टाचार जैसी समस्या इस कदर फैल गयी है। कि हर छोटे–से–छोटे काम के लिए हमें मूल्य देना

होता है। जिन लोगों के हाथों में देष को दिषा निर्देष करने का कार्य सौंपा गया है वो सुविधा भोगी होकर अपने कर्तव्यों से ही वंचित होते जा रहे है। आज भी देष से नक्सलवाद नही खत्म हो रहा है देष के कुछ राज्य जैसे– छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र में अक्सर नक्सली हमले हो रहे है। सर्जिकल स्ट्राइक के बावजूद सीमा पर लगातार गोलाबारी और हिंसक घटनाएँ बढ़ रही है।

निष्कर्ष– निष्कर्षतः मैं यही कहूँगी कि वर्तमान परिपेक्ष्य में हमारी राजव्यवस्था में अच्छाईयाँ तो बहुत है परन्तु इसके बावजूद राजव्यवस्था का संचालन बहुत हद तक दोषपूर्ण है। कही दोषपूर्ण चुनाव प्रक्रिया है तो कही दोषपूर्ण न्यायपालिका कही दोषपूर्ण षिक्षा प्रणाली है, तो कही आरक्षण की समस्या कही बढ़ती महगाई है तो कही पेयजल की समस्या तो कही रोजगार की, इसी कारण आये दिन दंगे, हड़ताल देखे जा रहे है।

लेकिन इसमें दोष केवल सरकार का ही नहीं है दोष है तो उन लोगों का जिनके ऊपर सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना का कार्यभार डाला गया है। अगर हाथ की चार ऊगलियाँ भष्टाचार, घूसखोरी और अपने स्वार्थसिद्धि में डुबी रहेगी तो एक अकेला अगूँठा किस प्रकार अपने काम को सही दिषा दे सकता है? अगर देष का हर नागरिक चाहे वह कोई भी कार्य कर रहा हो, किसी भी पद पर विराजमान हो यदि सभी को अपने देष से प्रेम होता तो सभी अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और लगन के साथ करते पर ऐसा नहीं है।

आप स्वयं से पूछिएँ क्या एक षिक्षक, बैंक कर्मचारी, कार्यालय कर्मचारी, कचहरी, संसदीय सदस्य इत्यादि जगहों पर जितने भी लोग कार्यरत है क्या सभी ईमानदारीपूर्वक देषप्रेम की भावना से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, जवाब मिलेगा नही। मैं ये नहीं कहती की सभी लोग ऐसे हैं पर ईमानदार लोगों की संख्या कम है। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हम सभी को मिलकर, ईमानदारी से, देषप्रेम की भावना से ओत–प्रोत होकर अपने–अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना होगा, तब जाकर हर सुविधा आम नागरिक तक पहुँचेगी, भेदभाव की नीति समाप्त होगी, न कही दंगे होंगे न कही हड़ताल। इसके अलावा राज्यसकार और केन्द्रसरकार को चाहिए कि अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान को आधार मानकर जनता जर्नादन की समस्याओं का अविलम्ब दूर करने का प्रयास करे। तब जाकर भारत सोने की चिड़िया और विष्वगुरु कहलाएगा।

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कष्चिद् दुःख भाग्भवेत्।।

(वैदिक संस्कृत साहित्य का इतिहास)

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. नीतिवाक्ययृत में राजनीति, एम.एल.शर्मा
2. प्राचीन भारतीय शासन पद्वति, ए.एस. अलतेकर
3. भारतीय प्रषासन, डॉ. पी.डी.शर्मा
4. भारतीय राजषास्त्र प्रणेता, डॉ. श्यामलाल पाण्डेय
5. भारत में श्रमकल्यण व सामाजिक सुरक्षा, डॉ. चतुर्भुज
6. भारतीय अर्थव्यवस्था, के.पी. सुन्दरम् व रूद्रदत्त
7. वर्तमान राजनीतिक विचारधाराऐं, ओ.पी.गुप्त
8. हिन्दू राजतन्त्र, श्री राम शर्मा
9. वैदिक संस्कृत साहित्य का इतिहास